शताब्दी समारोह सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति का कार्यकाल 14.4.1993 तक बढ़ा दिया गया है। स्थायी समिति की अवधि भी 14-4-1993 तक बढ़ा दी गई है। इन समितियों का पुनर्गठन करने सम्बन्धी संकल्पों और कार्यकाल बढ़ाए जाने सम्बन्धी संकल्पों की एक-एक प्रति संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट 163, अनुपत्र संख्या 30]

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिये छात्रावास

1622. **श्री अजीत जोगी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए अब तक निर्मित छात्रावासों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निर्मित लड़कों के लिए छात्रावासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सुविधा से लाभान्वित छात्र-छात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ इन राज्यों को 1990-91 और 1991-92 वर्ष के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ; और

(ङ) क्या राज्यों से इस धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अब तक क्रमशः 51 और 296 छात्रावास निर्मित/निर्माणाधीन हैं।

(ख) अनु० जाति के लड़कों के लिए 1990-91 के दौरान उ० प्र० और मध्य प्रदेश में क्रमशः 8 और 27 छात्रावास निर्मित/निर्माणाधीन थे ।

(ग) लाभान्वित हुई/लाभान्वित होने वाली अनुसूचित जाति की लड़कियों की संख्या उत्तर प्रदेश में 2120 है और मध्यप्रदेश में 10430 है । लाभान्वित हुए/लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति के लड़कों की संख्या उत्तर प्रदेश में 400 और मध्यप्रदेश में 600 है ।

(घ) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को क्रमशः 28,90,250 रु० और 1,27,17,750 रु० और मध्य प्रदेश राज्य सरकार को क्रमशः 3,06,60,000 रु० और 2,07,25,500 रु० निर्मुक्त किए गए थे ।

(ङ) प्रदत्त राशि का उपयोग करने के लिए सामान्यतः दो से 3 वर्ष लग जाते है ।

भाषाई अल्पसंख्यकों की सुविधाएं

1623. **कुमारी आलिया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने की सुविधाएं प्रदान कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या इस संबंध में अल्पसंख्यक आयोग का परामर्श लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्टों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस संबंध में किए गये प्रावधानों का विवरण होता है ।

अब तक ऐसी 28 रिपोर्टें सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं। ये प्राप्य दस्तावेज हैं ।